कम रोजगार मिला है और 8.9.91 के जनसत्ता अखबार की यह खबर है कि "डिग्री प्राप्त चार लाख महिलाओं में से सिर्फ डेढ़ लाख को नौकरियां मिलां"। सम्पूर्ण भारतीय कामकाजी महिलाएं सिर्फ चार प्रतिशत है। देश में जैसे-जैसे औद्योगिकीकरण और प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो महिला औसत रोजगार में भी कमी आई है। उद्योग के क्षेत्र में 1971 और 81 के बीच में जो कमी आई है वह 2.37 परसेंट है और भारी उद्योग में भी 1970 से 75 तक रोजगार में.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR); Thank you, thank you. You have made your point. Thank you. ...*(interruptions)*... Please take your seat. Mr. Vijay Darda.

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं सिर्फ यह कहना...देश के हर बड़े शहर में अलग से महिला रोजगार कार्यलय खोले जायें जिससे कि महिला बेरोजगारों की संख्या का पता लगाया जा सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You have taken six minutes, Madam. Mr. Vijay Darda. Kindly take three mir.iiCes. I am helpless.

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र): सर, मैं आपसे हाथ जोड़ लेता हूं कि आप दीन में दो और जोड़ दीजिए और पांच कर दिजीए।

THE VICE-CBAiRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I can't take that decision

श्री विजय जे. दर्डा: सर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका व सदन का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

चूंकि आप व्यवस्त थे इसलिए मैं रूक गया था।

THE VICE-CHAIRMAN: Please continue. My ear is towards you, my eyes are with him!

Deaths of Children due of Malnutrition in Different Parts of the Country

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर दिलाने जा रहा हूं जो मानव मभ्यता के ऊपर एक कलंक है और जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे को चोट लग जाए, वह गिर जाए तो हमारा दिल सकपका जाता है। लेकिन यहां पर हजारों बच्चे मौत के मुंह में सो रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाएं ही रही हैं किंतु मैं स्पैसिफिक बात आपको बताना चाहूंगा। मेलघाट एक ऐसी जगह है जहां पर आदिवासी कोटक् जाति के लोग रहते हैं। मेलघाट काकरीब दो हजार वर्ग मील का इलाका जंल से आच्छदित है। वहां परिवहन पर न कोई परिवहन के साधन है और न ही स्वास्थ्य संबंधी लोगों को जानकारी है। इस भाग में हर साल वर्ष होने के कारण बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1986 से इस क्षेत्र में कुपोषण के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मौत की खबरें आ रही हैं।

सन् 1991 में 294 बालक मौत के मुंह में सो गए। 1992 में 391, 1993 में 823 अबोध बच्चे कुपोषण की बलि चढ़ गए। इसके परिणावस्वरूप मेलघाट अखबारों की सुर्खियों में आ गया। 1995 और 96 में 1832 आदिवासी बच्चे कुपोषण की चपेट में आकर अपने प्राण गवां चुके हैं। यह हमारे लिए हार्ष की बात है। सरकार सोई हुई है और वह मौत की सौदागर बन गई है। इतनी भंयकर घटना होने के बावजूद भी उन आदिवासी परिवारों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इतनी बड़ी घटना घट रही है लेकिन हम नहीं जानते कि सरकार किन कामों में लगी हुई है। आज इतना महत्वपूर्ण विषय है, कहां पर हमारे लोग हैं? उन्हें यहां होना चाहिए था, समझना चाहिए था और तत्काल इसका निदान करना चाहिए था। आप जानते हैं कि मुंबई उच्च न्यायालय में इस संबंध में तीन याचिकायें दायर की गई थीं। उन पर 11 अप्रैल, 1997 में अदालत ने फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि अप्रैल से सितम्बर 1997 के बीच कम से कम एक वक्त सरकार आदिवासियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए। संविधान की धारा 38 के तहत सरकार के लिए सामाजिक न्याय एंव आर्थिक समानता सभी को उपलब्ध करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। संविधान की धारा 47 के तहत कहा गया है कि पोषण तथा जीवन स्तर ऊंचा उठाने एंव सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का स्तर सुधारने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। न्यायलय ने तीनों यानिकाओं का निपटारा करते हुए तथा संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को मलघाट में नवजीवन योजना के प्रभावी क्रियान्यवयन के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे। किन्तु क्या हुआ?

इसलिए सर, मैं चाहूंगा और मेरी मांग है कि वेशेषज्ञ चिकित्सकों तथा अधिकारियों का एक दल उस क्षेत्र में भेजा जाए जो वहां जाकर यह देखे कि समस्या क्या है? अगर आवश्यकता पड़े तोसांसदों का एक दल भी वहां भेजा जाए क्योंकि करीब करीब तीन हजार बच्चों की वहां मौत हुई है और हाल ही में दो बच्चे वहां पर मरे हैं।

महोदय, यह कुपोषण का प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You please concUide. You have already taken four minutes.

SHRI VIJAY J. DARDA: Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you, Mr. Darda. So kind of you. Shri John F. Fernandes.

Denial of Visa to Indian Scientists and their expulsion by U.S.A.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. My submission is regarding post-Pokhran nuclear fall-out. Internationally the impact of this fall-out is more on USA. We have seen in the last week or so that one of our scientists. Dr. Chidambaram, who wanted to pursue his academic mission in the United Nations to explain the Indian point of view on the nuclear issue *vis-a-vis* not signing the NPT and the;CTBT, was denied a US visa. That country has every sovereign right or duty to deny the visa to any person. I am not disputing that. I am on a different point. The UN Headquarters is in New York and the visa to the delegates to the UNO is given by the Government of USA. So, my request to the Government of India—our Prime Minister is likely to visit the UNO in September this year—is that we have to make a request that the UN Headquarters should be stationed either in Africa or in Asia. Among many other nations India is the only country which pays its dues to the United Nations unlike the USA, one of the so-called superpowers, one of the powers who is policing the whole world. I would request the Prime Minister to consider this issue seriously. If Dr. Chidambaram is needed by the UN mission at New York, he will not be permitted. I want this anomaly to be removed. The Government of India should take up this issue strongly that the UN Headquarters should be shifted out of USA and it should be stationed in India.

I think the Government of India and the people of India will not object to give them one Island in Andaman and Nicobar. We have hundreds of them. I hope the Government of India will take up this issue very strongly and see to it that the developing countries are not belittled and no arms are twisted to sign NPT and CTBT. Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I want to associate myself with this issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I have three more names with me on this issue. Let them first speak. Then you can associate yourself with this issue. Prof. Malhotra.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, जो फर्नाडिस साहब ने सवाल उठाया है कि चिदम्बरम् साहब को वीसा नहीं दिया गया और जब यू.एन. ओ. बनाया गया था उसमें इस तरह की कमिटमेंट दी गई थी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। परन्तु जो सवाल मैंने दिया था वह यह था कि 7 वैज्ञानिकों को जो इस समय अमरीका में काम कर रहे हैं, निकल जाने के लिए कहागया है और यह बताया गया है कि 75 दूसरे वैज्ञानिकों को निकालने के लिए नोटिस दिए जाने की बात की जा रही है। यह जो अमरीका का रवैया है, इसकी सारे सदन को निंदा करनी चाहिए। अमरीका की यह कार्यवाही न केवल पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग की है, बुली करने की है क्योंकि हमने अणु विस्फोट किया है इसलिए हमारे वैज्ञानिक जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको निकाल देना या भेज देना, यह अमरीका का बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। चीन को अमरीका ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। वह चार-चार विस्फोट अपने यहां करते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके साथ मिल कर अभी क्लिंटन साहब ने